



विकसित भारत

प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से नागरिकों और सरकार को करीब लाना
(खंड-II)

“

हम,

PROGRESS OF THE PEOPLE...

PROGRESS BY THE PEOPLE...

PROGRESS FOR THE PEOPLE...

के मंत्र को लेकर चल रहे हैं।

हमारा उद्देश्य,
नया भारत बनाने का है,
भारत को विकसित
बनाने का है।



विषय सूची

नवाचार केंद्र

- 10 आधार - चेहरे के प्रमाणीकरण से जीवन परिवर्तन
- 16 पीएम स्वनिधि योजना - आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना
- 22 भारत में पोषण शासन में बदलाव
- 28 भारत में ई-कॉमर्स में क्रांतिकारी बदलाव

नवाचार राज्य

- 36 सरल डिजिटल समाधानों के साथ लैंड म्यूटेशन को सुव्यवस्थित करना
- 42 सौर ऊर्जा का उपयोग करके ग्रामीण जल आपूर्ति को बदलना
- 48 नागालैंड में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना
- 54 शिक्षा में परिवर्तन-सरकारी उच्च विद्यालय में क्षमता विकास

विषय सूची

जिलों में नवाचार

62 सतत जल समाधान के लिए धमतरी की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

68 पार्वती पुरम मान्यम में स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता का एक नया युग

74 कोरापुट की ग्रामीण सशक्तिकरण यात्रा

80 एस्पायर कुमारी-महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए विकास को बढ़ावा देना





नवाचार केंद्र



“
**आज का
नवाचार
कल
का उद्योग है**

आधार-चेहरे के प्रमाणीकरण से जीवन परिवर्तन





भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआई) ने देश में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत करके पहचान सत्यापन में क्रांति ला दी है, यह एक अत्याधुनिक समाधान है जो भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा, सुगमता और सुविधा को बढ़ाता है। 15 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई और जून 2022 में विस्तारित की गई, इस एआई -संचालित तकनीक ने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित, स्पर्श रहित और कुशल सत्यापन संभव हुआ है। यह अध्याय भारत में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक की तकनीकी दक्षता, व्यापक पैमाने पर अपनाए जाने और परिवर्तनकारी प्रभावों पर प्रकाश डालता है।

अपनाई गई कार्यनीतियाँ

कोई बाहरी उपकरण या प्रमाणीकरण नहीं



विभिन्न क्षेत्रों और जनसांख्यिकीय खंडों में व्यापक परीक्षण किए गए। बैंकों में ई-केवाईसी प्रक्रियाओं से लेकर पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तक, मौजूदा प्रणालियों में फेस ऑथेंटिकेशन को एकीकृत करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों, बैंकों और सरकारी एजेंसियों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का विस्तार हुआ।

भारतीय जनसांख्यिकी के अनुरूप एक एआई /एमएल-आधारित समाधान तैयार किया गया। मॉडल को नागरिकों के विविध डेटासेट पर संचालित किया गया, जिसमें विभिन्न आयु समूहों, एथनीसिटी और पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखा गया।

सहमति-आधारित दृष्टिकोण पर बल दिया गया, जिससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित हुई।



उपलब्धियाँ

- 77 संस्थाओं ने फेस ऑथेंटिकेशन को अपनाया, जिसमें बैंक, पीएम-किसान जैसी सरकारी योजनाएँ, दूरसंचार सेवाएँ और कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। यह तकनीक एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ता दूर से ही स्व प्रमाणन कर सकते हैं।
- यह मजदूरों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, जिन्हें फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन से परेशानी होती थी। टचलेस मोडैलिटी ने समावेशिता को बढ़ाया, जिससे पिछड़े समुदायों को जरूरी सेवाओं तक बेहतर पहुँच मिली।
- पारदर्शिता में वृद्धि और धोखाधड़ी में कमी, खास तौर पर पीएम-किसान जैसी कल्याणकारी योजनाओं में, जहाँ फेस ऑथेंटिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचे, जिससे प्रतिरूपण और भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

समग्र प्रभाव

फेस प्रमाणीकरण की तकनीक के कार्यान्वयन ने पीएम-किसान, पीएमएवाई (शहरी), पीएम-जेएवाई और जीवन प्रमाण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसके तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक सफल लेनदेन हुए हैं। इस तकनीक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, जिससे मैनुअल सत्यापन के लिए आवश्यक समय और प्रयास कम हो गए हैं। इसने प्रशासनिक लागतों को घटाकर और धोखाधड़ी वाले लेनदेन को कम करके आर्थिक लाभ भी लाया है, जिससे अधिक आर्थिक विकास में योगदान मिला है। इसके अतिरिक्त, फेस प्रमाणीकरण ने बैंक खातों, सब्सिडी और पेंशन तक पहुँच को सरल बनाकर वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और ग्रामीण आबादी जैसे सबसे पिछड़े समुदायों को लाभ पहुँचाया है। इस नवाचार ने सरकारी सेवाओं और वित्तीय योजनाओं को उन लोगों के लिए अधिक सुलभ बना दिया है जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।



**देश का सामान्य नागरिक,
अब Empowered और
Encouraged Feel
करने लगा है।**

अब उसे इसकी चिंता नहीं
होती कि उसे किसी
ताकतवर आदमी के
यहां चक्कर लगाने
होंगे, उसकी सहायता
लेनी होगी।





पीएम स्वनिधि योजना

आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना



1 जून, 2020 को शुरू की गई दूरदर्शी पहल का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना है। यह योजना ₹.80,000 तक के कोलैटरल-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। यह डिजिटल लेनदेन के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी और प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह विक्रेताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वीकार्यता की भावना सुनिश्चित करती है। मूल रूप से मार्च 2022 में समाप्त होने वाली, इस योजना को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ऋण अवधि दिसंबर 2024 में समाप्त होगी।

अपनाई गई कार्यनीति

विक्रेताओं के पुनर्भुगतान ब्यौरे के आधार पर ₹.80,000 तक के कोलैटरल-मुक्त ऋण प्रदान किए गए। डिजिटल वित्तीय साक्षरता एक प्रमुख फोकस बन गई जिसने विक्रेताओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया। विक्रेताओं को एक मान्यता प्राप्त पहचान प्रदान करने के लिए परिचय बोर्ड लागू किया गया। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, विक्रेताओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दी गई। अनुशंसा पत्र के माध्यम से सुव्यवस्थित, मांग-संचालित पंजीकरण प्रक्रिया अपनाई गई। चरणबद्ध ऋण दृष्टिकोण ने समय पर पुनर्भुगतान को बढ़ावा दिया और ऋण उपलब्धता में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप 66 लाख प्रथम-अवधि, 20 लाख द्वितीय-अवधि और 3.9 लाख तृतीय-अवधि ऋण वितरित किए गए। वार्षिक 7% ब्याज सब्सिडी ने शीघ्र पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित किया, जिससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिला। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए स्वनिधि से समृद्धि पहल शुरू की गई।



उपलब्धियाँ

- इस योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण उपलब्धता के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। उल्लेखनीय रूप से 95% विक्रेताओं ने इस योजना के माध्यम से अपना पहला बैंक ऋण प्राप्त किया, जिनमें से कई पहले अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर थे।
- सक्रिय निगरानी प्रणाली और प्रोत्साहन पुनर्भुगतान संरचना ने 2022 में जारी किए गए ऋणों के लिए एनपीए दर को घटाते हुये 9% के स्तर पर रखा, जो समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने में योजना की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- ऋण और डिजिटल लेनदेन की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर, इस योजना ने 62% स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय स्थिरता में सुधार की रिपोर्ट करने में मदद की।
- 42 लाख डिजिटल रूप से सक्रिय स्ट्रीट वेंडर्स ने 341 करोड़ डिजिटल लेनदेन किए, जिनकी कीमत रु.3.81 लाख करोड़ थी, इस योजना ने स्ट्रीट वेंडिंग क्षेत्र के औपचारिकीकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल 164 करोड़ रु. कैश-बैंक प्रोत्साहन के रूप में वितरित किए गए हैं।
- स्वादिष्ट व्यंजन की आधुनिक दुकान (एसवीएडी) पहल ने स्ट्रीट वेंडर्स को स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जिसके तहत 10,000 से अधिक विक्रेताओं को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 22 करोड़ रु की बिक्री हुई है।
- दमन में, "सिल्वन दीदी" पहल के तहत महिला स्ट्रीट वेंडर्स ने कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मासिक आय रु.3,000 से बढ़कर रु.40,000-रु.45,000 हो गया है।

समग्र प्रभाव

पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स की आय के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे महिला उद्यमियों को काफी सशक्त बनाया गया है।

दमन नगर परिषद द्वारा महिला विक्रेताओं को दिए गए समर्थन जैसी पहलों ने उन्हें अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक मान्यता प्रदान की। इस योजना के समावेशी दृष्टिकोण ने यह भी सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित सबसे पिछड़े समुदायों को लाभों की समान सुविधा मिले, जिसमें 75% लाभार्थी 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के थे, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी जनसांख्यिकी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 2,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें अपने व्यवसायों को और विकसित करने और विस्तार करने के लिए कौशल प्राप्त हुए।

बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं सहित वित्तीय संस्थानों को कम एनपीए दरों और सशक्त ग्राहक जुड़ाव से लाभ हुआ। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने विक्रेता पंजीकरण, ऋण वितरण और प्रभावी शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करके योजना की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



“

हमारा एक ही
संकल्प होता है-

**नेशन फर्स्ट,
राष्ट्रीय हित
सर्वोपरि।**

हमारा भारत महान बने,
हम इसी संकल्प को
लेकर कदम उठाते हैं।





**भारत में पोषण
शासन में परिवर्तन**



भारत में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, खास तौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए, लंबे समय से एक चुनौती रही है।

1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना की शुरुआत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। हालाँकि, इस कार्यक्रम को अनियमित डेटा संग्रह, देरी से निगरानी और लक्षित इंटरवेंशन करने में कठिनाई जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा। 2018 में, सरकार ने पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए पोषण अभियान शुरू किया। हालाँकि, डेटा संग्रह में देरी और अपूर्ण जानकारी ने वास्तविक समय की निगरानी उपकरण की आवश्यकता को उजागर किया, जिससे पोषण ट्रैकर का विकास हुआ।

अपनाई गई कार्यनीति

डेटा संग्रह में देरी और अपूर्ण जानकारी के कारण रियल टाइम की निगरानी उपकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर लॉन्च किया, जो एक स्मार्टफोन आधारित उपकरण है जो सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत सेवाओं को केंद्रीकृत करता है। इसने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, छोटे बच्चों और किशोरियों सहित लाभार्थियों का डेटाबेस बनाए रखा, और आधार-आधारित सत्यापन, ऑफलाइन पंजीकरण, दैनिक सेवा ट्रैकिंग, डब्ल्यूएचओ-मानक विकास निगरानी और एसएमएस अलर्ट जैसी स्वचालित सुविधाएँ प्रदान कीं। 24 भाषाओं में उपलब्ध इस ऐप ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हितधारकों के लिए कार्यों को भी सुव्यवस्थित किया है।

उपलब्धियाँ

- पोषण ट्रैकर ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों सहित 100 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया, जिससे निर्बाध ट्रेकिंग और सहायता के लिए डेटा को समेकित किया गया।
- इसने 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ा, जिससे रियल टाइम में डेटा संग्रह और प्रबंधन संभव हुआ, जिससे शासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने में वृद्धि हुई।
- ट्रैकर ने डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार मासिक रूप से 80 मिलियन से अधिक बच्चों के विकास की निगरानी की, जिससे पोषण संबंधी आवश्यकताओं की शीघ्र पहचान और लक्षित इंटरवेंशन की सुविधा मिली।
- ओपन एपीआई की सुविधा देकर, पोषण ट्रैकर ने अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ एकीकरण किया, जिससे एक सुसंगत कल्याण इको-सिस्टम को बढ़ावा मिला और राज्य और केंद्रीय पहलों के बीच कुशल डेटा साझाकरण हुआ।
- प्लेटफॉर्म ने दैनिक कार्यों को स्वचालित करके और लाभार्थी प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरण प्रदान करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया, जिससे पंजीकरण, सेवा ट्रेकिंग और निगरानी की प्रक्रिया सरल हो गई।
- पोषण ट्रैकर में व्यापक डैशबोर्ड और हीट मैप्स ने राज्य और केंद्रीय अधिकारियों को पोषण संकेतकों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान की, जिससे सम्पूर्ण भारत में डेटा-संचालित शासन और साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों को समर्थन मिला।



समग्र प्रभाव

पोषण ट्रैकर ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित 100 मिलियन से अधिक लाभार्थियों के लिए सूचना को केंद्रीकृत करके भारत में पोषण शासन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकों के साथ विकास निगरानी में क्रांति ला दी, जिससे कुपोषण के लिए लक्षित इंटरवेंशन संभव हो सका। 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़कर इसने रियल टाइम डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान की, जिससे देश भर में पारदर्शिता और कुशल सेवा सुपुर्दगी को बढ़ावा मिला। ओपन एपीआई एकीकरण ने अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ डेटा को सहजता से साझा करने की सुविधा प्रदान की, जिससे एक सुसंगत कल्याणकारी इको-सिस्टम का निर्माण हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, स्वचालित लाभकारी प्रबंधन, कार्य शेड्यूलिंग और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना। व्यापक डैशबोर्ड और हीट मैप्स के साथ, अधिकारियों ने डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिससे नीति प्रभाव में वृद्धि हुई। इस डिजिटल दृष्टिकोण के माध्यम से, पोषण ट्रैकर ने निरंतर निगरानी के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया और वैश्विक स्तर पर इसी तरह की पहल को प्रेरित किया।



“

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास

इससे देश को प्रगति के लिए एकजुट करने तथा विकास के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने में बहुत लाभ हुआ है।





**भारत में ई-कॉमर्स में
क्रांतिकारी बदलाव**



ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक दूरदर्शी पहल है।

इसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में छोटे व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान करके डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है। ओपन आर्किटेक्चर मॉडल पर विकसित ओ. एन. डी. सी. भुगतान और पहचान सत्यापन में भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सफलता को दोहराने का प्रयास करता है, इस बार खुदरा व्यापार क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ओ.एन.डी.सी. ई-कॉमर्स परिदृश्य में विकेंद्रीकरण, अनबंडलिंग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है। यह प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से ध्यान हटाकर अधिक समावेशी, प्रोटोकॉल-आधारित प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका लक्ष्य ई-कॉमर्स को अधिक सुलभ बनाना है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्बाध लेनदेन संभव हो सके। एक खुले और प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देकर ओ. एन. डी. सी. प्लेटफॉर्म को सहजता से बातचीत करने की अनुमति देता है, जो भारत के डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है। नेटवर्क छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएमई) को सशक्त बनाता है, उपभोक्ता विकल्प को बढ़ाता है और व्यवसायों के लिए प्रारंभिक समस्याओं को कम करके नवाचार को बढ़ावा देता है। प्रमुख सरकारी प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत होने के कारण, ओ. एन. डी. सी. व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, ऋण उपलब्धता को तेज करता है, और डिजिटल कॉमर्स में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

उपलब्धियाँ

- प्रति माह 12 मिलियन से अधिक ऑर्डर प्रोसेस किए गए।
- सम्पूर्ण भारत में 700,000 से अधिक विक्रेता सक्रिय हो गए।
- ओ.एन.डी.सी. ने फैशन और राइड-हेलिंग सहित 10 से अधिक श्रेणियों में काम किया।
- नेटवर्क ने 1,100 से अधिक शहरों और कस्बों तक अपनी मौजूदगी का विस्तार किया।
- 7,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) इसमें शामिल हुए।

सफलता की कहानियाँ

तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्री विद्या हैंडलूम्स ने ओ.एन.डी.सी. में शामिल होने के बाद बिक्री में 46% की बढ़ोतरी और मुनाफे के मार्जिन में 15% की बढ़ोतरी देखी।

कोल्ड-प्रेस्ड ऑयल में विशेषज्ञता रखने वाले ग्रामीण ब्रांड कल्पनिल नेचुरल्स ने ओ.एन.डी.सी. के माध्यम से स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुँच का विस्तार किया।

बेंगलुरु में नम्मा यात्री ने ड्राइवरों के लिए एक निश्चित सदस्यता शुल्क की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप आय में वृद्धि हुई और ऑटोरिक्षा ड्राइवरों के लिए कमीशन कम हो गया।

पश्चिम बंगाल के जन्नापुर की नई एग्रीवर्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने अपने मशरूम की खेती के व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ओएनडीसी का लाभ उठाया, जिससे बिक्री और उपलब्धता दोनों में सुधार हुआ।



समग्र प्रभाव

ओ.एन.डी.सी. ने छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्धता को सुलभ बनाकर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध लेन-देन को सक्षम करके भारत के ई-कॉमर्स परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। 12 मिलियन से अधिक मासिक कार्य-आदेश और 7,00,000 सक्रिय विक्रेताओं के साथ, इस पहल ने एसएमई को सशक्त बनाया है, उपभोक्ता विकल्प को बढ़ाया है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रमुख सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण की सुविधा प्रदान करके, ओ.एन.डी.सी. ने प्रारंभिक बाधाओं को कम किया है और डिजिटल कॉमर्स में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। श्री विद्या हैंडलूम और कल्पनिल नेचुरल्स जैसी सफलता की कहानियाँ बिक्री और उपलब्धता पर सकारात्मक प्रभाव को उजागर करती हैं। ओ.एन.डी.सी. 2047 तक भारत के “विकसित भारत” के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में एक प्रमुख चालक है।





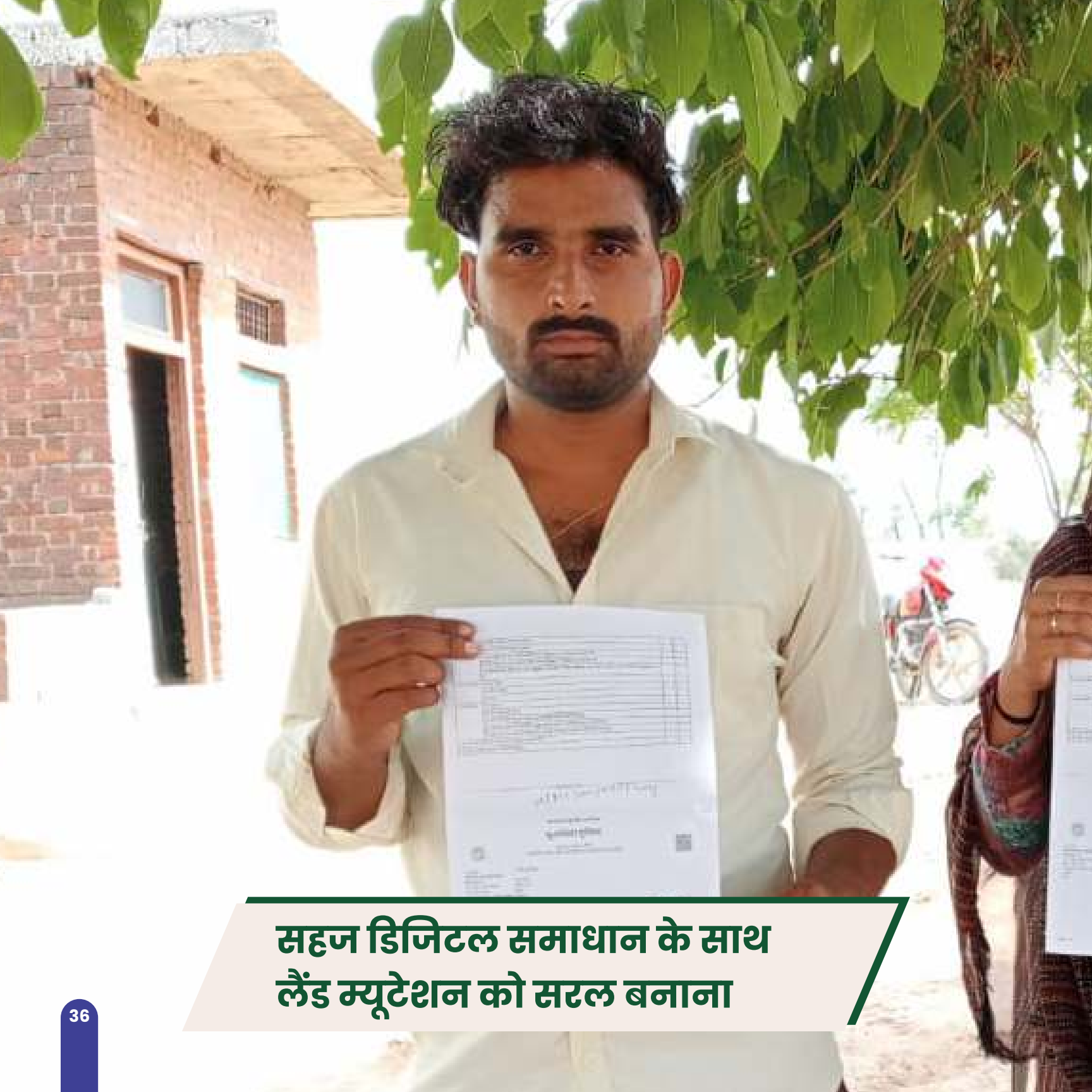
**नवाचार
राज्य**

“

**आज पूरी दुनिया की दृष्टि
भारत पर है...
भारत के युवाओं पर है।**

दुनिया... बुद्ध के इस देश
के साथ... Mother of
Democracy के साथ...
कंधे से कंधा मिलाकर
चलना चाहती है।





**सहज डिजिटल समाधान के साथ
लैंड म्यूटेशन को सरल बनाना**



पहल का शुभारम्भ

साइबर तहसील पेपर लेस और फेसलेस लैंड म्यूटेशन के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य “सिंगल विंडो” के माध्यम से म्यूटेशन की सेवा प्रदान करना है। यह राज्य की सीमाओं को शामिल करता है और मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों को सेवा प्रदान करता है।

अपनाई गई कार्यनीति

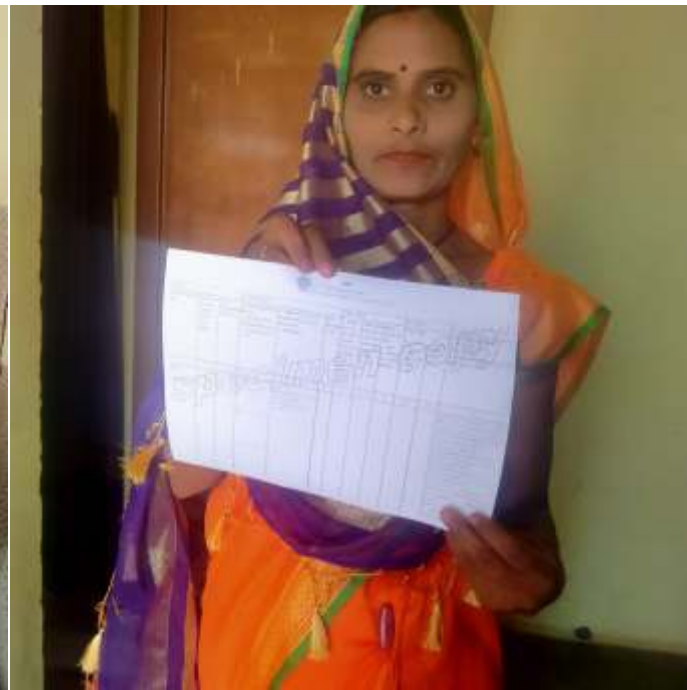
साइबर तहसील राजस्व विभाग के मौजूदा राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) का एक विस्तारित मॉड्यूल है और इसे अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश के राज्य डेटा सेंटर में संचालित किया गया है। एप्लिकेशन को डॉट नेट तकनीक का उपयोग करके डिजाइन और विकसित किया गया। इसमें 4 ये सिस्टम एकीकृत हैं: आरसीएमएस-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, संपदा-आरजीआरएस डिपार्टमेंट, एसएएआरए-फील्ड यूजर एप्लिकेशन और डब्ल्यूईबीजीआईएस - भूमि अभिलेख सॉफ्टवेयर।

लैंड म्यूटेशन के पारंपरिक माध्यमों में चुनौतियाँ:

पारंपरिक दृष्टिकोण में, खरीदारों को बिक्री विलेख के बाद म्यूटेशन के लिए आवेदन करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में कई टचपॉइंट शामिल थे, जिसमें प्रमाणित बिक्री विलेख प्रति के लिए पंजीकरण कार्यालय जाना, म्यूटेशन आवेदन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तहसील कार्यालय, रिपोर्ट के लिए पटवारी, प्रमाणित प्रतियों के लिए कियोस्क और पक्षों को नोटिस की भौतिक सेवा शामिल थी। पक्षों को तहसील न्यायालय में स्वयं उपस्थित होना भी आवश्यक था। औसतन, म्यूटेशन आदेश पारित होने में 70 दिन लगे (डेटा स्रोत: आरसीएमएस, 01/04/2023 से 31/03/2024)। आरसीएमएस आदेश के बाद भी, भूमि अभिलेख को तुरंत अपडेट नहीं किया गया, जिसके लिए अपडेट के लिए अलग-अलग आवेदन और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता थी।

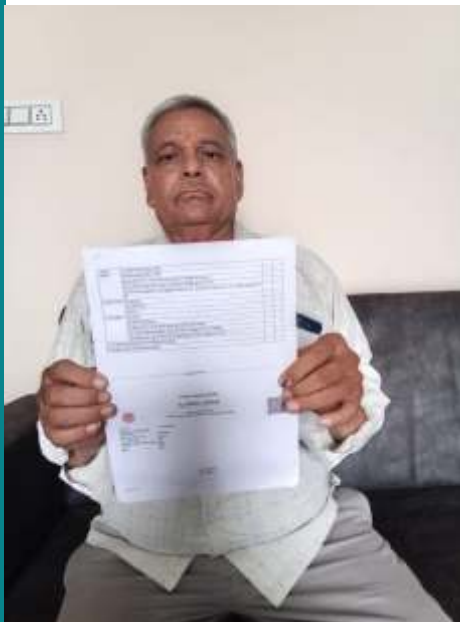
उपलब्धियाँ

- आयकर निर्धारण की तरह ही क्षेत्रीय सीमाओं को सुव्यवस्थित किया गया, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल हो गई। यह पूर्ण भूमि पार्सल के लिए सभी निर्विवाद, भार-मुक्त बिक्री और उपहार रजिस्ट्री मामलों पर लागू हुआ।
- खरीदारों को तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय, बिक्री विलेख निष्पादन के समय म्यूटेशन आवेदनों को सीधे पंजीकरण कार्यालय में संसाधित किया गया।
- बिक्री विलेख निष्पादित होने के बाद, पंजीकरण पोर्टल (सम्पदा) से डेटा स्वचालित रूप से राजस्व पोर्टल (आरसीएमएस) में स्थानांतरित हो गया, जिससे निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित हुआ।
- खरीदार, विक्रेता और संबंधित ग्रामीणों को एसएमएस के माध्यम से स्वचालित ऑनलाइन नोटिस भेजे गए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक भी था। पटवारी रिपोर्ट अब समयबद्ध तरीके से (10 दिनों के भीतर) ऑनलाइन प्राप्त की जाती थी।
- 99% से अधिक मामलों में, जहाँ कोई आपत्ति नहीं थी और पटवारी रिपोर्ट अनुकूल थी, म्यूटेशन आदेश तुरंत जारी किया गया और भूमि रिकॉर्ड अपडेट किया गया।
- इस प्रणाली ने म्यूटेशन आदेश जारी होने के बाद भूमि रिकॉर्ड अद्यतनीकरण में 100% अनुपालन सुनिश्चित किया।
- इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन (0755-2525800), ईमेल सहायता (rcms-gr@mp.gov.in), व्हाट्सएप सहायता (9407299468) और ऑनलाइन टिकट जारी करने की सुविधा उपलब्ध थी।



समग्र प्रभाव

साइबर तहसील पहल ने पेपर लेस और फेसलेस सेवा प्रदान की, जिसका उद्देश्य एक "सिंगल विंडो" के माध्यम से म्यूटेशन सेवाओं को शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ पेश करना था। इसने क्षेत्रीय सीमाओं को समाप्त कर दिया और पटवारी-रहित अमल प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल भूमि रिकॉर्ड अपडेट सुनिश्चित किया। इस प्रणाली ने भौतिक संपर्क को कम किया, जिससे तेजी से सेवा प्रदायगी संभव हुई और आवेदकों को म्यूटेशन आदेश की एक प्रति और भूमि रिकॉर्ड में अनुपालन प्रदान किया गया। इसने धारा 109 और 110 के तहत मामलों का निवारण किया, जहां किसी पूरे खसरा या भूखंड के अधिकार या हित बिना किसी विभाजन के हस्तांतरित किए जा रहे थे। मामलों को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से राउंड-रॉबिन तरीके से साइबर तहसीलदारों को आवंटित किया गया, जिससे मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो गया। आवेदकों को सूचनात्मक पैम्फलेट के साथ केस पंजीकरण के बारे में समय पर सूचना मिली। साइबर तहसील के कार्यान्वयन ने दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया, म्यूटेशन केस भार को 25% तक कम किया और न्यूनतम मानव संसाधनों के साथ 230 से अधिक राजस्व न्यायालयों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च उपयोगकर्ता संतुष्टि प्राप्त हुई।



पारंपरिक तहसील की तुलना में साइबर तहसील का प्रभाव

उत्तराधिकार (म्यूटेशन) के लिए निपटान समय

साइबर तहसील में उत्तराधिकार (म्यूटेशन) के लिए निपटान समय औसतन 20 दिन है, जबकि पारंपरिक प्रक्रिया के तहत औसतन 70 दिन लगते हैं।

उत्तराधिकार(म्यूटेशन) के बाद भूमि-अभिलेख (खसरा/नक्शा) को अपडेट करना

साइबर-तहसील में वास्तविक समय में म्यूटेशन के बाद 100% भूमि-अभिलेख तुरंत अपडेट हो जाते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण में केवल 20% भूमि-अपडेट दो महीने के समय (46 से 128 दिनों तक) में अपडेट होते हैं। तीन महीनों में (1.03.2024 से 30.06.2024 तक) 41,746 रजिस्ट्री का आदेश दिया गया है और 20 दिनों से कम समय में भूमि अपडेट में 100% मामलों का अनुपालन किया गया है।

“

जब देशवासियों की
इतनी विशाल सोच हो,
इतने बड़े सपने हों,
इतने बड़े संकल्प झलकते हों,

**तब हमारे भीतर एक
नया संकल्प दृढ़
हो जाता है,
हमारा आत्मविश्वास
नई ऊंचाई पर पहुँच
जाता है।**





**सौर ऊर्जा का उपयोग
ग्रामीण जल आपूर्ति में परिवर्तन**



हर घर जल के अपने दृष्टिकोण के साथ जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य को अपनाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा चालित जल आपूर्ति योजनाएं शुरू कीं, जो सभी के लिए जल सुनिश्चित करने के लिए एक टिकाऊ और कम लागत दृष्टिकोण है। इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य गरीबों को पानी की कमी से मुक्ति दिलाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

चुनौतियाँ

उत्तर प्रदेश में, इसकी विशाल ग्रामीण आबादी और सीमित घरेलू जल की उपलब्धता के साथ, चुनौती न्यूनतम लागत में सुलभ, टिकाऊ पेयजल उपलब्ध कराना था। बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र, जो जल जनित बीमारियों से ग्रस्त हैं, प्रमुख लक्षित क्षेत्र बन गए।

अपनाई गई कार्यनीतियाँ

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन ने नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के तहत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा प्रबंधित सौर ऊर्जा संचालित जल आपूर्ति योजनाएँ शुरू कीं। इस पहल ने दूरदराज और ऑफ ग्रिड ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय जल उपलब्धता की अनूठी चुनौतियों का एक अभूतपूर्व समाधान पेश किया, जहाँ पारंपरिक बिजली सीमित या अनियमित थी।



उपलब्धियाँ

- उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति अवसंरचना में सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग ने पूरे राज्य में जल उपलब्धता की स्थिति को बदल दिया है।
- इस मिशन में 75 जिलों, 826 ब्लॉकों, 58,287 पंचायतों और 96,921 गांवों को आच्छादित करने वाली 44,142 जलापूर्ति योजनाएं शामिल हैं, जो 2.66 करोड़ घरों में 17 करोड़ लोगों की ग्रामीण आबादी को सेवा प्रदान करती हैं।
- सौर ऊर्जा संचालित योजनाएं जल पम्पिंग के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, पारंपरिक बिजली आधारित जल आपूर्ति प्रणालियों की सीमाओं को पार करती हैं।
- सौर ऊर्जा संचालित योजनाओं ने परिचालन लागत को कम किया और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दिया।
- महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा किए, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में समुदायों को लाभान्वित किया।
- घरेलू अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकल्प को प्रोत्साहित किया गया, विशेष रूप से जहां बिजली ग्रिड तक पहुंच सीमित है।
- वर्तमान में, 67,013 गांवों में 33,157 सौर ऊर्जा संचालित योजनाएं सक्रिय हैं, जो 1.67 करोड़ घरों को आच्छादित करती हैं और 13.3 करोड़ लोगों को लाभान्वित करती हैं।

समग्र प्रभाव

उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सौर ऊर्जा को अपनाने से 900 मेगावाट बिजली की बचत हुई, जिससे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड पर बोझ कम हुआ। अगर ये जलापूर्ति योजनाएं पारंपरिक बिजली पर निर्भर होतीं, तो उन्हें एक बार कनेक्शन की लागत 2,503 करोड़ रुपये और वार्षिक बिजली व्यय 1,050 करोड़ रुपये वहन करना पड़ता। हालांकि, सौर ऊर्जा को अपनाने से, इस पहल से 30 वर्षों में कुल 37,395 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। सौर ऊर्जा संचालित योजनाओं ने प्रति घर वार्षिक संचालन और रखरखाव लागत को भी घटाकर 1,220 रुपये कर दिया, जो बिजली आधारित योजनाओं के लिए आवश्यक 2,531 रुपये से 52% कम है। सौर ऊर्जा को अपनाने से पर्यावरण को लाभ हुआ, जिससे प्रति वर्ष 13 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई, जो 2070 तक भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य का समर्थन करता है। ये ऑफ-ग्रिड समाधान दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी साबित हुए, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए एक विश्वसनीय जल आपूर्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया, जिससे भारत के एसडीजी और जलवायु लक्ष्यों में योगदान मिला। 67,013 गांवों में 33,157 सौर ऊर्जा संचालित योजनाओं के साथ पहल का महत्वाकांक्षी पैमाना दुनिया भर में ग्रामीण जल आपूर्ति में अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित था।



“

भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में,
किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम हैं।

**इन सपनों को पूरा करने के लिए
सरकार के पास स्पष्ट रोडमैप है,
स्पष्ट विजन है।**



नागालैंड में

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त बनाना





नागालैंड की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सीमित बुनियादी ढांचे, कठिन भूभाग और बिखरी हुई आबादी से जूझ रही है, जिससे कई लोगों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक सीमित पहुंच है। इसका समाधान करने के लिए, नागालैंड सरकार ने 2022 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएमएचईएस) शुरू की, जो सभी नागरिकों के लिए कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा प्रदान करती है। राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आयुष्मान भारत पीएम - जेएवाई से बाहर रखे गए परिवारों सहित 396,002 परिवारों को शामिल करते हुए, सीएमएचईएस का उद्देश्य नागालैंड के एसडीजी विजन 2030 के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के लगभग सभी परिवार सस्ती स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकें।

अपनाई गई कार्यनीति

राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पीएम-जेएवाई लाभार्थियों सहित विभिन्न लाभार्थी श्रेणियों को समेकित करने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म को अपनाया गया।

दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एंड-टू-एंड आईटी-आधारित क्लेम प्रोसेसिंग प्रणाली लागू की गई।

कवरेज को अधिकतम करने के लिए डेटा-संचालित आउटरीच और जागरूकता अभियान चलाए गए।

एसएचजी और आशा जैसी स्थानीय संस्थाओं के साथ सहयोग किया गया, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद मिली, पंजीकरण और उपयोग दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी समुदाय पीछे न छूट जाए।



उपलब्धियां

- सीएमएचआईएस ने पात्र परिवारों का लगभग 100% कवरेज हासिल किया, जिसमें पेंशनभोगियों जैसे पहले से वंचित समूह और आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई से बाहर रखे गए लोग शामिल हैं।
- योजना की आईटी-आधारित क्लेम प्रणाली ने अधिकृत उपचार प्रक्रियाओं में पर्याप्त वृद्धि की है, जो अपने पहले वर्ष में 27,361 प्रक्रियाओं तक बढ़ गई है।
- दावा राजस्व को पुनर्निवेशित करके, सार्वजनिक अस्पतालों ने बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार किया, जिससे एक वर्ष में राजस्व में 374% की वृद्धि हुई, जो ₹.5 करोड़ से बढ़कर ₹.19 करोड़ हो गई।
- डायलिसिस रोगियों जैसी पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों का सामना कर रहे लाभार्थियों को वित्तीय राहत मिली क्योंकि सीएमएचआईएस ने अस्पताल में भर्ती होने के सभी खर्चों को शामिल किया।
- इस योजना ने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, डिजिटल उपकरणों के साथ सशक्त बनाया, जो डेटा एक्सेस और क्लेम प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित करते हैं।
- डेटा-संचालित आउटरीच प्रयासों, पंजीकरण अभियानों और स्थानीय संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से, सीएमएचआईएस ने निजी अस्पताल के दावों में 249% की वृद्धि देखी।
- सीएमएचआईएस के एंड-टू-एंड आईटी प्लेटफॉर्म और नागालैंड हेल्थ प्रोटेक्शन सोसाइटी (एनएचपीएस) के साथ साझेदारी ने धोखाधड़ी का पता लगाने और शिकायत तंत्र के साथ प्रभावी शासन सुनिश्चित किया।
- राज्य द्वारा आवंटित स्वास्थ्य निधि और बीमा प्रीमियम संरचनाओं के साथ सीएमएचआईएस के अभिनव वित्तपोषण मॉडल ने वित्तीय स्थिरता स्थापित की।

सफलता की कहानियाँ

नागा अस्पताल प्राधिकरण, कोहिमा (एनएचएके): एनएचएके एक मामूली डिस्पेंसरी से नागालैंड के सबसे बड़े सार्वजनिक अस्पताल में तब्दील हो गया। सीएमएचआईएस निधियों का उपयोग करके, इसने रोगी देखभाल को बेहतर बनाया, बुनियादी ढाँचे को उन्नत किया, और पर्यावरण अभियान एवं कर्मचारियों के प्रोत्साहन जैसी कल्याणकारी पहलों का समर्थन किया, जिससे विकास एवं सामुदायिक जुड़ाव दोनों को बढ़ावा मिला।

जिला अस्पताल मोन: शुरुआती वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, जिला अस्पताल मोन सीएमएचआईएस निधियों के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से आगे बढ़ा। अस्पताल ने उपकरणों को उन्नत किया, आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती की, और सेवाओं में सुधार किया, सक्रिय कार्ड जनरेशन ड्राइव के साथ रोगी पंजीकरण में वृद्धि हुई और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित हुई।



समग्र प्रभाव

नागालैंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएमएचआईएस) का राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने परिवारों के लिए जेब से होने वाले खर्चों को काफी कम कर दिया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक कैशलेस पहुँच प्रदान की गई। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म और एंड-टू-एंड आईटी-आधारित क्लेम प्रोसेसिंग सहित योजना के अभिनव दृष्टिकोण ने स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया। सीएमएचआईएस ने वंचित आबादी तक पहुँच का विस्तार किया, जिसके तहत लगभग 100% कवरेज हासिल किया गया। इसने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए राजस्व बढ़ाया और सेवा प्रदायगी में सुधार किया। इस पहल ने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाया, जिससे प्रशासनिक बोझ कम हुआ। रणनीतिक संसाधन जुटाने और रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की गई। सीएमएचआईएस ने स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके ग्रामीण समुदायों में आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान की। शासन और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्र ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की। एनएचएके और जिला हॉस्पिटल मोन जैसे अस्पतालों की सफलता की कहानियों ने योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को पेश किया। कुल मिलाकर, सीएमएचआईएस ने नागालैंड के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

“
**भारत आज एक विकासशील
देश भी है और उभरती हुई
शक्ति भी है।**

हम गरीबी की चुनौतियां
भी समझते हैं और
प्रगति का रास्ता
बनाना भी जानते हैं।



शिक्षा में बदलाव

सरकारी उच्च विद्यालय में क्षमता विकास





आंध्र प्रदेश में सरकारी उच्च विद्यालयों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के नेतृत्व वाली क्षमता विकास पहल ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए स्मार्टबोर्ड, टैबलेट और इंटरैक्टिव सामग्री को अपनाने पर जोर देने के एक परिवर्तनकारी प्रभाव का नेतृत्व किया है। छात्र एआई, आईओटी और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार कौशल से अधिक सुसज्जित हो गए हैं, जबकि शिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ हुआ है।

अपनाई गई कार्यनीतियाँ

डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए सैचुरेशन अप्रोच अपनाया गया था, जिसमें स्मार्टबोर्ड, टैबलेट और हाई-स्पीड इंटरनेट सहित स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को हाई स्कूलों में उपलब्ध कराया गया था।

छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग को बढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तकों के साथ सिंक्रनाइज किए गए डिजिटल संसाधन पहले से लोड किए गए थे।

डिजिटल बुनियादी ढांचे, उपयोग और टीचिंग-लर्निंग प्रथाओं की प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए नियमित रूप से असाइनमेंट और रिपोर्ट तैयार की गईं।

प्रेरणा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई और पुरस्कृत किया गया।

हार्डवेयर समस्या निवारण और सॉफ्टवेयर सहायता के लिए इंजीनियरिंग छात्रों को शामिल करते हुए प्रशिक्षुता कार्यक्रम लागू किए गए।

उपलब्धियाँ

- छात्रों द्वारा टैबलेट का औसत उपयोग 15 मिनट से बढ़कर 110 मिनट प्रतिदिन हो गया।
- शिक्षकों द्वारा टैबलेट का औसत उपयोग 24 मिनट से बढ़कर 85 मिनट प्रतिदिन हो गया।
- शिक्षकों द्वारा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल (स्मार्टबोर्ड) का उपयोग 80 मिनट से बढ़कर 165 मिनट प्रतिदिन हो गया।
- गणित में 'ए' ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 55,390 से दोगुनी होकर 1,06,676 हो गई।
- कक्षा नौ के छात्रों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में 8.33% सुधार हुआ।
- छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों से परिचित कराया गया।
- इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखरखाव में सहायता की, टैबलेट, स्मार्टबोर्ड और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं के निवारण में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
- इंजीनियरिंग के छात्रों को व्यावहारिक कौशल, बी.टेक डिग्री के लिए क्रेडिट और रु.12,000 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में वृद्धि हुई।
- छात्रों के लिए 9.53 लाख टैबलेट, शिक्षकों के लिए 80,000 टैबलेट और 6,200 हाई स्कूलों में 62,000 कक्षाओं में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लगाए गए।



समग्र परिणाम

इस पहल ने स्कूलों में व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे लगाकर डिजिटल शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाया। छात्रों के बीच टैबलेट का काफी उपयोग हुआ, जिससे डिजिटल उपकरणों को अपनाने में वृद्धि हुई। छात्रों को भविष्य के कौशल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स से परिचित कराया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में आगे रहें। शिक्षकों को इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसरों से व्यापक प्रशिक्षण मिला, जिससे डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी क्षमता बढ़ी।

असाइनमेंट-आधारित मूल्यांकन ने डिजिटल बुनियादी ढांचे की जवाबदेही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया। इंजीनियरिंग के छात्रों ने स्कूल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाए रखने, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या निवारण और डिजिटल लर्निंग का समर्थन करके बहुमूल्य रियल वर्ल्ड का अनुभव प्राप्त किया, साथ ही अकादमिक क्रेडिट और स्टाइपेंड भी अर्जित किया।

गेमीफाइड, पाठ्यपुस्तक-सिंक्रोनाइज्ड ई-कंटेंट के एकीकरण ने छात्रों के लिए सीखना, आकर्षक और इंटरैक्टिव बना दिया। इंजीनियरिंग छात्रों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से डिजिटल उपकरणों के रख-रखाव के लिए एक स्थायी मॉडल स्थापित किया गया, जिससे दीर्घकालिक कार्यक्षमता सुनिश्चित हुई। पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्टता को मान्यता देने से नवाचार को बढ़ावा मिला और स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। शिक्षण में प्रेरणा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए समय-समय पर सम्मानित भी किया गया।





जिलों में नवाचार

“

**मेरा ध्येय अपने देश और
अपने लोगों के विकास के लिए काम करना है।**

इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है,
खासकर इसलिए क्योंकि
हमें अभी बहुत लंबा
रास्ता तय करना है।



An aerial photograph showing a large, calm pond in the center. To the left and bottom, there is a cluster of small houses with various roof colors (red, grey, blue). To the right and top, there are large, vibrant green agricultural fields. The pond is surrounded by a mix of greenery and some trees.

सतत जल समाधान

के लिए धमतरी की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना



विजन

वर्षाजल संग्रहण और भंडारण को अधिकतम करना
जियोटैगिंग के माध्यम से सभी जल-बचत संरचनाओं का मानचित्रण और ट्रैकिंग करना
जल संरक्षण और संचयन प्रणालियों के निमण के लिए विज्ञान-समर्थित योजना बनाना
जल संरक्षण प्रयासों में जागरूकता बढ़ाना और समुदायों को शामिल करना
भूजल स्तर को बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को कम करना,

मुख्य कार्यक्षेत्र

- जल संरक्षण और वर्षाजल संचयन को बढ़ावा देना
- जल निकायों का मानचित्रण और सूचीकरण
- वैज्ञानिक जल संरक्षण योजनाएँ विकसित करना
- जल शक्ति केंद्रों की स्थापना
- गहन वनरोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाना
- जल संरक्षण और स्थायी प्रथाओं के महत्व के बारे में समुदाय को शामिल करना और शिक्षित करना।
- जलाशयों की सफाई और जीर्णोद्धार
- भूजल पुनर्भरण के लिए परित्यक्त बोरवेलों को पुनर्जीवित करना

अपनाई गई कार्यनीति

बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नियमित संसाधन आकलन किए गए, ताकि निर्णय लेने के लिए डेटा की सटीकता सुनिश्चित हो सके।

योजना प्रक्रिया में किसानों, स्थानीय समुदायों, सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया।

एकीकृत बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रयासों को मिलाकर एक एकीकृत रणनीति बनाई गई।

जल प्रबंधन पहलों को अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़कर एक अभिसरण रणनीति अपनाई गई, ताकि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

उपलब्धियां

- सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक एनएच्यूआईएम रिपोर्ट के अनुसार, धमतरी जिला 2021 से 2023 तक क्रिटिकल से सेमी-क्रिटिकल श्रेणी में आ गया है।
- वन विभाग ने महानदी बेसिन में 30 धाराओं और 364 किलोमीटर में 648 जल निकासी लाइनों का शोधन किया, रु.25.85 करोड़ की लागत से 72,444 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया।
- मटियाबहारा गांव में 1,129 हेक्टेयर के लिए जीआईएस-आधारित प्रबंधन योजना विकसित की गई, जिससे जल संसाधन प्रबंधन में सुधार हुआ और जंगल की आग को रोका गया।
- 17 करोड़ रु. के निवेश से मनरेगा के तहत 112 ग्राम पंचायतों में 498 कायाकल्प और पुनर्भरण संरचनाएं पूरी की गईं।
- 40 लाख रु. की शहरी तालाब सफाई परियोजना चिन्हित की गई, जिसमें दरार वाले क्षेत्रों को ठीक किया गया, जिसमें छह तालाबों को सफाई के लिए उपयुक्त माना गया।
- जीआईएस-आधारित अध्ययन ने धमतरी शहर में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 25 कार्रवाई योग्य उपायों की पहचान की, जिससे लक्षित व्यय संभव हुआ।
- शहरी आवास योजना के अनुसार 834 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया, तथा 238 और निर्माणाधीन हैं।
- 300 एकड़ बंजर भूमि पर वनरोपण किया गया, जिससे कृषि-वानिकी पहल के माध्यम से 220 महिलाओं को आजीविका मिली।
- जल जागरण अभियान ने भूजल में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाई, जलदूत ऐप के माध्यम से पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया।
- ग्राम पंचायत परसतराई ने धान की खेती से तिलहन और दलहन की खेती की ओर रुख किया, जिससे एक वर्ष में भूजल स्तर में 130 फीट से 80 फीट तक सुधार हुआ।
- सिरसिदा स्टॉप डैम सह कॉजवे का निर्माण रु.2.46 करोड़ की लागत से किया गया, जिससे 80 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई और सात गांवों को कनेक्टिविटी मिली।
- औद्योगिक बोरवेल में 16 फ्लो मीटर लगाए गए और 156 वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित की गईं, जिनमें से 99 उद्योगों ने अनुपालन की आवश्यकता थी।
- एनएचआई, एडीबी और रेलवे परियोजनाओं के साथ 124 अंतःक्षेपण कुओं और 28 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया।
- पीएम जनमन पहल के तहत, कमार पीवीटीजी में बस्तियों की जीआईएस मैपिंग से तालाबों, बांधों और होमस्टे वृक्षारोपण का निर्माण हुआ, जिससे मिट्टी की नमी और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि हुई।
- पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 472 एकड़ में 33 जल-संभर संरचनाएं बनाई गईं, जिससे 105 किसानों को लाभ हुआ और भूजल स्तर 2 मीटर बढ़ गया।

समग्र प्रभाव

एनआईसी ने धमतरी जिले के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक जल संरक्षण योजना विकसित करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और क्यूजीआईएस, आर्कजीआईएस और गूगल इमेजरी जैसे उन्नत भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग किया। पहल की शुरुआत मौजूदा जल निकायों और वर्षा जल संचयन संरचनाओं की पहचान और गणना के साथ हुई। जिले भर में कुल 1,740 जल निकायों का मानचित्रण किया गया। इसरो/भुवन पोर्टल से उच्च रिजॉल्यूशन की छवियों ने इन जल निकायों को जियो-टैग करने और डूबे हुए क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद की। नदियों, सहायक नदियों, जलाशयों, बांधों और नदी-बांधों पर आवश्यक डेटा एकत्र किया गया और उन्हें भू-स्थित मानचित्रों में बदल दिया गया। इन मानचित्रों में निर्माण वर्ष, नदी बेसिन के नाम, जल भंडारण क्षमता और सिंचाई कवरेज जैसे विवरण शामिल थे। वर्षा-ऋतु से पहले और बाद में जल स्तर दिखाने वाले अतिरिक्त मानचित्र बनाए गए। भूजल की स्थिति और संभावित मानचित्रों के साथ-साथ प्रमुख नदी जलग्रहण क्षेत्र के मानचित्र भी विकसित किए गए। इस प्रयास ने धमतरी में सतत जल प्रबंधन और संरक्षण की नींव रखी।



“

आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में
जिस तेजी से काम कर रहा है,
वो अभूतपूर्व है।

**भारत की स्पीड,
भारत की स्केल,
अनप्रेसिडेन्टेड है।**



पार्वतीपुरम मान्यम

में स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता का एक नया युग





उत्तर-पूर्वी आंध्र प्रदेश में बसा पार्वतीपुरम मान्यम जिला अपने बीहड़ इलाकों और दूरदराज के गांवों के लिए जाना जाता है, जो आवश्यक सेवाओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। यह जिला ऐतिहासिक रूप से शिशु और मातृ मृत्यु दर की उच्च दरों से जूझ रहा है, जो अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और भौगोलिक अलगाव के कारण और भी बदतर हो गई है। कम साक्षरता दर इन समस्याओं को और बढ़ा देती है, जिससे महिलाएँ और बच्चे विशेष रूप से कुपोषण और एनीमिया जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

पहल की शुरुआत

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को 10 से नीचे लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जिला-व्यापी पहल प्रिज्म (PRISM) 10 की शुरुआत की गई। इसने प्रिवेंटिव केयर, शीघ्र निदान और समय पर समाधान पर ध्यान केंद्रित करके मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर भी बल दिया, अंततः बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा दिया और जिले में शिशु और मातृ मृत्यु दर दोनों को कम किया।

अपनाई गई कार्यनीति

गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर की निगरानी, आयरन सप्लिमेंट्स का वितरण सुनिश्चित करने और उचित पोषण को बढ़ावा देने के लिए मंडल और ग्राम सचिवालयम स्तर पर एनीमिया एकरान कमेटियों (एएसी) का गठन।

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर नजर रखने, प्रसवपूर्व जाँच, टीकाकरण और पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के दत्तक ग्रहण अधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत निगरानी।

गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ सहयोग।

जागरूकता अभियान चलाने, स्वास्थ्य सेवा वितरण की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर सुधार का समर्थन करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को शामिल किया गया।



उपलब्धियाँ

- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 2021-2022 में 24 से घटकर 2023-2024 में 8 हो गई।
- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 2021-2022 में 128 से घटकर 2023-2024 में 82 हो गई।
- पूर्ण टीकाकरण कवरेज 2021-2022 में 46.19: से बढ़कर 2023-2024 में 97.77% हो गया।
- गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार हुआ, जनवरी 2024 तक किसी भी महिला का एचबी <8 ग्राम/डीएल नहीं हुआ।
- गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की निगरानी और उसका समाधान करने के लिए एनीमिया एक्शन कमेटीयों का पुनर्गठन किया गया।
- मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ और टेलीमेडिसिन सेवाएँ सुदूर क्षेत्रों तक पहुँची हैं, जिससे प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित हुई है।
- आपातकालीन और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए रक्त बैंक उन्नयन और एम्बुलेंस खरीद की पहल की गई।
- भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए सलूर और जीएल पुरम में गर्भवती महिलाओं के लिए ठहरने के स्थान और प्रसव प्रतीक्षा कक्ष स्थापित किए गए।
- गिरि वैद्य केंद्रलु (आदिवासी स्वास्थ्य केंद्र) की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार हुआ।
- उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं की अधिक संख्या को समायोजित करने के लिए बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) का विस्तार किया गया।

समग्र प्रभाव

प्रिज्म (PRISM) 10 पहल ने पार्वतीपुरम मन्यम में शिशु और मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी की। इसने मोबाइल इकाइयों और टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया। टीकाकरण दर में उछाल आया, जो लगभग 98% तक पहुँच गया। प्रभावी पोषण इंटरवेंशंस के कारण गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार हुआ। परियोजना के तहत, आदिवासी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना ने हाशिए पर पड़े समुदायों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच का विस्तार किया। बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाई के विस्तार सहित बुनियादी ढाँचे के उन्नयन ने बढ़ती स्वास्थ्य सेवा माँगों का समाधान किया।

प्रिज्म (PRISM) ने एक स्थायी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए सरकारी प्रयासों, सामुदायिक जुड़ाव और प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक एकीकृत किया।





**हमारा विश्वास है कि किसी भी पहल
की सफलता में
जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण
कारक होती है।**





कोरापुट

की ग्रामीण सशक्तिकरण यात्रा



विजन

- स्थानीय महिलाओं के उत्थान और प्रेरणा के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की शक्ति का उपयोग करना।
- स्थानीय कारीगरों और व्यापक बाजारों के बीच संपर्क स्थापित करना, ताकि अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन किया जा सके।
- स्वयं सहायता समूहों को सतत विकास के लिए संपन्न लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) में बदलना।
- नए बाजार अवसरों को खोलने के लिए संपर्क और संसाधनों को बढ़ाना।
- एक उज्ज्वल, हरित भविष्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल कृषि और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना।

अपनाई गई कार्यनीति

गांवों के पास मध्यम स्तर की प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिससे ग्रामीण कृषि उपज के उपयोग में सुधार हुआ।

जिला प्रशासन ने स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, सीआईएमएपी और आईसीआरआईएसएटी जैसे अनुसंधान संगठनों के साथ भागीदारी की।

एसएचजी को बेहतर फसल प्रसंस्करण और विपणन के लिए उन्नत तकनीकों और अनुसंधान की सुविधा प्राप्त हुई।



उपलब्धियां

- ग्रामीण औद्योगिक पार्क परिसर (आरआईपीसी) ने एसएचजी महिलाओं के लिए एक मंच तैयार किया, जिससे उन्हें एसएमई में बदलने में मदद मिली।
- एसएचजी को वित्तीय और बाजार संपर्क, विकास योजनाओं और क्षमता निर्माण तक पहुंच मिली।
- बाजरा, चावल, हल्दी और नींबू घास जैसे स्थानीय संसाधनों को संसाधित किया गया और मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए गए।
- किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया गया, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिला।
- ईंटों और पेवर ब्लॉकों के लिए निर्माण इकाइयों ने किफायती गांव के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए डिजिटल नकद लेनदेन और पीओएस मशीनें शुरू की गईं।
- एसएचजी उत्पादों का स्थानीय और ऑनलाइन विपणन किया गया, जिसमें अमेज़ॅन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग से फसल प्रसंस्करण में सुधार हुआ और एसएचजी के लिए बेहतर बाजार पहुंच हुई।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बाजरा, हल्दी और लेमनग्रास जैसी फसलों के प्रसंस्करण में कौशल हासिल किया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई।
- आईसीआरआईएसएटी जैसे संगठनों के साथ साझेदारी ने बाजरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने में मदद की, जिससे मैनुअल श्रम में कमी आई।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे रक्षा संस्थानों के साथ बड़े पैमाने पर गठजोड़ करके अपनी बाजार पहुंच का विस्तार किया।

समग्र प्रभाव

कोरापुट में ग्रामीण औद्योगिक पार्क परिसर (आरआईपीसी) ने 14 ब्लॉकों में स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में सुधार हुआ जिससे बिक्री में वृद्धि हुई। महिलाएँ अलग-थलग उत्पादक से सशक्त उद्यमी बन गईं, जिनके पास प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार संपर्क तक पहुँच थी। स्थानीय किसानों को उनके उत्पादों के मूल्यवर्धित प्रसंस्करण से लाभ हुआ, जिससे बेहतर मूल्य और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित हुई। इस परियोजना ने स्थानीय बुनियादी ढाँचे और बाजार पहुँच में संधारणीय, कमी को पूरा किया, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिला। इसने महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए एक अभिनव मंच बनाया, जिसमें सीएसआईआर, ओयूएटी और ओआरएमएस जैसे संस्थानों के साथ मिलकर वित्तीय सहायता, बाजार संपर्क और क्षमता निर्माण प्रदान किया गया, जिससे एसएचजी को छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) में बदलने में मदद मिली। बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ, मसाले और बेकरी सामान जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर इसने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया। मिशन शक्ति कैफे, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम उत्पादन और जलीय कृषि गतिविधियों जैसी अन्य पहलों ने आर्थिक स्थिरता में योगदान दिया।



“
यह भारत के विकास का अमृत काल है।
आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा
हुआ है।





**एस्पायर कुमारी-महिलाओं और युवाओं
के सशक्तिकरण के लिए विकास को बढ़ावा देना**



पहल का शुभारम्भ

कन्या कुमारी के जिला प्रशासन के नेतृत्व में एस्पायर कुमारी पहल का उद्देश्य उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है। रणनीतिक प्रशिक्षण, सलाह और बाजार तक पहुंच के माध्यम से, यह समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए स्थानीय आर्थिक चुनौतियों का समाधान करता है। यह मॉडल वंचित समुदायों के उत्थान और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता वाले अन्य जिलों के लिए एक अनुकरणीय ढांचे के रूप में कार्य करता है।

अपनाई गई कार्यनीति

पहल ने कुमारी हैकाथॉन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिससे छात्रों को स्थानीय चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

युवाओं और महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और ई-कॉमर्स को कवर करते हुए अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

50 स्वयं सहायता समूहों को कानूनी रूप से पंजीकृत संस्थाओं में बदलने में मदद करके उन्हें सशक्त बनाया।

स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन सुनिश्चित करने के लिए नाबाई और स्टार्टअपटीएन जैसी राज्य-व्यापी इनक्यूबेशन केंद्रों और फंडिंग एजेंसियों के साथ सहयोग किया।

चुनौतियों का सामना

व्यावसायिक ज्ञान और विपणन रणनीतियों की कमी के कारण सीमित बाजार पहुंच

प्रतिभागियों के बीच उद्यमिता और डिजिटल कौशल के विभिन्न स्तरों पर कौशल में अंतर

क्षेत्र में सीमित औद्योगिक अवसरों जैसी आर्थिक बाधाओं ने स्नातकों और महिला उद्यमियों के लिए बाधाएं उत्पन्न कीं



उपलब्धियाँ

- कुमारी हैकथॉन परियोजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में पाँच छात्र स्टार्टअप पंजीकृत हुए, जिससे कई नवीन उत्पाद तैयार हुए।
- इस हैकथॉन में 4,647 छात्रों ने भाग लिया, जिन्हें 273 टीमों में संगठित किया गया।
- 11 एसएचजी सफलतापूर्वक पंजीकृत कंपनियों में परिवर्तित हो गए, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधि में योगदान मिला।
- नांजिल नाडु कानी ट्राइबल वूमन क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु एससी/एसटी स्टार्टअप फंड के तहत 25 लाख रुपये का इक्विटी निवेश हासिल किया।
- दो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप, वेवो क्राफ्ट्स और क्यूरेली फूड्स को व्यापार विस्तार के लिए टैनसीड फंडिंग में 15 लाख रुपये मिले।
- मार एप्रैम इनक्यूबेशन सेंटर में उत्पाद विकास सहायता के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई।
- स्वयं सहायता समूहों ने डिजिटल उपकरण और भुगतान प्रणाली अपनाना शुरू किया, जिससे उनकी बाजार पहुंच और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई।

समग्र प्रभाव

इस पहल का कई मोर्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा, विशेषतौर पर युवाओं, महिलाओं और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में। 4,600 से अधिक छात्र समस्या-समाधान गतिविधियों में लगे हुए थे, अपने कौशल को निखार रहे थे और नवाचार को बढ़ावा दे रहे थे। कार्यक्रम ने नए रोजगार के अवसर पैदा करके स्थानीय आर्थिक चुनौतियों का समाधान किया, साथ ही युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाया। महिलाओं, खासकर सबसे पिछड़े समुदायों से, लक्षित प्रशिक्षण और समर्थन के माध्यम से आत्मविश्वास और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कानूनी रूप से पंजीकृत इकाई बनने का अधिकार दिया गया, जिससे उनकी विश्वसनीयता और बाजार पहुंच बढ़ी। परिणामस्वरूप, प्रतिभागी एसएचजी ने प्रशिक्षण के छह महीने के भीतर 35% राजस्व वृद्धि देखी। इसके अतिरिक्त, इस पहल ने उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे समुदाय-संचालित विकास और स्थानीय जुड़ाव को बढ़ावा मिला।





सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग